सच कहने की ताकत

जालंधर ब्रीज

साप्ताहिक समाचार पत्र

• JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-2 • 23 SEPTEMBER TO 29 SEPTEMBER 2020 • VOLUME- 9 • PAGES- 4 • RATE- 3/- • www.jalandharbreeze.com • RNI NO.:PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
STUDY, WORK & SETTLE IN ABROAD
Low Filing Charges &
*Pay money after the visa
IELTS | STUDY ABROAD
CANADA AUSTRALIA USA
U.K SINGAPORE EUROPE
E-mail : ankush@innovativetechin.com • hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10, Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. • HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza, GT Road, Adjoining Lovely Professional University, Phagwara.
*T&C apply

ड्रग्स कनेक्शन

एनसीबी ने जारी किया दीपिका पादुकोण और टैलेंट एजेंसी के सी.ई.ओ. को समन

■ मुम्बई/ब्यूरो

सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मौत के बाद बॉलीवुड पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुशांत की मौत का जिम्मेदार पहले नेपोटिस्म को बताया गया। नेपोजिस्म को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था। कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर काफी गंभीर आरोप लगाये। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की दुनिया बहुत काली है। यहां के अंधेरे में लोग खो जाते हैं। कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है तो गलत पीआर करके उसे खत्म कर दिया जाता हैं। कंगना ने बॉलीवुड में मूवी माफिया का राज बताया। इसके बाद धीरे-धीरे बॉलीवुड की परत खुलती रही और सामने आया बॉलीवुड में फैली कैमिकल दुनिया का सच।

बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से ड्रग्स का कारोबार काफी बढ़ गया हैं। इस बात का खुलासा सुशांत की मौत की जांच के दौरान हुआ। जांच में कुछ बाते सामने आयी जिसमें एक ये थी कि सुशांत की प्रेमिका सुशांत को ड्रग्स देती थी। सुशांत को रिया ने ड्रग्स का आदी बना दिया था।

ड्रग्स की जांच के मामले रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक एक करके कई नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आये हैं। बॉलीवुड के 25 बड़े नामों का जिक्र है जिसका खुलासा अभी एनसीबी ने नहीं किया है लेकिन धीरे-धीरे कई नाम सामने आ रहे हैं। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह के बाद सुपरस्टार दीपिका पादुकोण का नाम भी सामने आया हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एनसीबी की पड़ताल में दीपिका का नाम भी सामने आने के बाद जैसे बॉलीवुड में भूचाल सा आ गया हैं। जिस पवित्र बॉलीवुड की संसज में जया बच्चन दुहाई दे रही थी कि कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, थाली में छेद कर रहे हैं... सभी तरह की थाली की सच्चाई सामने आ रही हैं।

दीपिका भारत की सबसे हाई पेद एक्ट्रेस हैं। दीपिका के नाम से ही सिनेमाघरों के सारे टिकट बिक जाते थे। जब दीपिका पादुकोण जैसी भारत की टॉप क्लास एक्ट्रेस का नाम ड्रग्स से जुड़ा तो एक बार सोचने की जरुरत है कि अभी और कौन कौन शामिल होगा। नाम सामने आने के बाद एनसीबा ने अपनी जांच तेज कर दी हैं।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोज् (एनसीबी) ने बॉलीवुड से जुड़े लोगों के में मादक पदार्थों के कथित सेवन के मामले की जांच के सिलसिले में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की प्रबंधक करिश्मा प्रकाश और एक च्टैलेंट प्रबंधक एजेंसी के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारी ने बताया कि एनसीबी दोनों से मंगलवार दोपहर को पूछताछ करेगी। उन्होंने बताया कि चितगोपेकर के डब्ल्यू ए एन टैलेंट प्रबंधक एजेंसी के सीईओ हैं और करिश्मा प्रकाश इस एजेंसी की कर्मचारी हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के दौरान बॉलीवुड हस्तियों के मादक पदार्थों के कथित तौर पर सेवन करने की बाते सामने आई, जिसकी अब जांच की जा रही है। राजपूत की च्टैलंट मैनेजरज् जया साहा से भी सोमवार को एनसीबी ने पूछताछ की थी। अधिकारी ने बताया कि उनसे पूछताछ के दौरान एनसीबी को मामले में कई बॉलीवुड हस्तियों की कथित भूमिकाओं की जानकारी मिली।

उन्होंने बतराया कि एनसीबी द्वारा पहले जिन लोगों से पूछताछ की गई, उनकी व्हाट्सएप चैट में मादक पदार्थों को लेकर हुई बातचीत के संकेत मिले हैं।

एनसीबी ने अब तक इस मामले में 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी शामिल हैं।

राजपूत बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में 14 जून में मृत मिले थे।

मैंने जिंदगी में कभी ड्रग नहीं ली, कानूनी लड़ाई लड़ूंगी- दीया मिर्जा

"मेरी छवि खराब करने की कोशिश है"

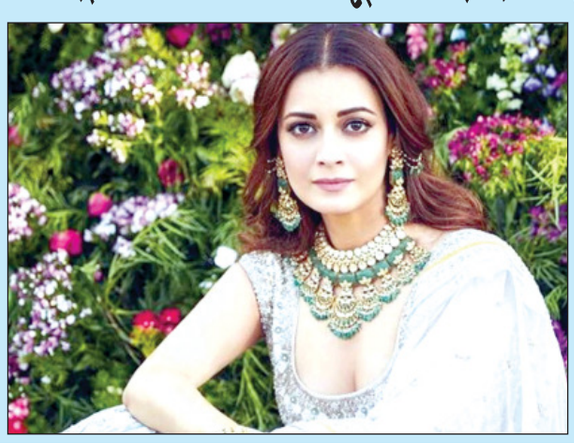

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

ड्रग्स केस में नाम आने पर दीया मिर्जा ने सफाई दी है। उन्होंने एक के बाद एक तीन ट्विट्स किए. उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी ड्रग नहीं ली है। जो भी खबरें चल रही है पूरी तरह से झूठी है। मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। कानूनी लड़ाई लड़ूंगी।

एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, अभिनेत्री दीया मिर्जा का नाम ड्रग्स केस में आया है। ड्रग्स पैडलर अनुज केशवानी ने दीया मिर्जा का नाम लिया है।

सूत्रों के मुताबिक, केशवानी ने बताया कि दीया की मैनेजर ड्रग्स खरीदती थी, इसके सबूत भी दिये हैं।

अब इस मामले में एनसीबी जल्द ही दीया मिर्जा को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है।

यूपी : बलिया में एक निरक्षर लड़की के बैंक अकाउंट में आए 10 करोड़ रुपये!

■ बलिया/ब्यूरो

यूपी के बलिया जिले में बांसडीह क्षेत्र की रहने वाली एक निरक्षर किशोरी के बैंक खाते में 10 करोड़ रुपये जमा होने से सनसनी फैल गई. किशोरी ने इस मामले में पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई का अनुरोध किया है।

बांसडीह इलाके के रूकूनपुरा गांव की सूबेदार साहनी की पुत्री सरोज ने मंगलवार को बताया कि उसका इलाहाबाद बैंक की बांसडीह शाखा में खाता हैं। वह कल खाते में लेनदेन करने बैंक पहुंची तो बैंक कर्मियों ने बताया कि उसके खाते में जमा धनराशि नौ करोड़ 99 लाख 4736 रूपये है। इस जानकारी के बाद किशोरी के होश उड़ गये. सरोज बांसडीह कोतवाली पहुंची और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी।

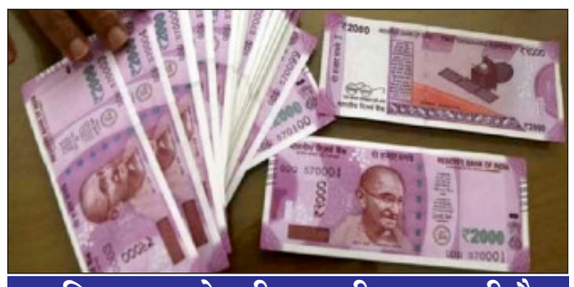

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

सरोज ने शिकायती पत्र में कहा है कि इलाहाबाद बैंक में साल 2018 में उसका खाता खुला है। दो वर्ष पूर्व ही कानपुर देहात जनपद के पाकरा गांव के नीलेश कुमार नाम के व्यक्ति ने उसे फोन कर प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर आधार कार्ड और फोटो देने को कहा जो उसने उसे दिये गये पते पर भेजे थे। उसे नहीं मालूम कि वह धन कहां से आया है। सरोज ने पुलिस को यह भी जानकारी दी है कि नीलेश के जिस मोबाइल नम्बर से उसकी बातचीत होती थी वह अब स्वीच ऑफ बता रहा है। इलाहाबाद बैंक की बांसडीह शाखा के प्रबंधक सरोज कुमार सिंह ने बताया कि सरोज के खाते में दस-बीस हजार करके कई बार राशि जमा हुई और निकले हैं. बांसडीह कोतवाली के निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

क्या कर्नाटक में होगी येदियुरप्पा की विदाई? भाजपा ने खबरों को किया खारिज, कही यह अहम बात

■ बेंगलुरु/ब्यूरो

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने मंगलवार को इन खबरों को बेबुनियाद और भ्रामक करार दिया कि मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को हटाकर राज्य में नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कैप्टन गणेश कार्णिक ने कहा कि कुछ टीवी चैनलों ने कथित रूप से खबर दी है कि मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का नेतृत्व बदला जा रहा है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कहा, भाजपा इस खबर का दृढ़ता से खंडन करती है। उन्होंने कहा, हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसी खबर बिल्कुल बेबुनियाद, गुमराह करने वाली और सच्चाई से दूर है। ऐसी अटकलें हैं कि येदियुरप्पा की उम्र को देखते हुए भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है। इन अटकलों को तब बल मिला जब हाल ही में 77 वर्षीय येदियुरप्पा नयी दिल्ली गये थे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों एवं भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा से भेंट की थी। ऐसी खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव या मार्च, 2021 में येदियुरप्पा द्वारा बजट पेश किये जाने के बाद उनके स्थान पर किसी और को लाया जा सकता है। कयास लगाये जा रहे हैं कि 75 साल की उम्र पार करने वाले नेताओं के प्रति भाजपा की नीति के तहत पार्टी लिंगायत नेता को राज्यपाल का पद देकर और उनके छोटे बेटे बी वाई विजयेंद्र को अहम पद देकर येदियुरप्पा की सम्मानजनक विदाई पर विचार कर कर रही है।

किसान बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस, प्रियंका गांधी ने पूछे ये सवाल

■ लखनऊ/ब्यूरो

देश में कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर राजनीति जारी है। विरोधी दल इसको लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं, कुछ राज्यों में किसान भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं. इसी बीच, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी केंद्र को अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रही हैं। प्रियंका ने मंगलवार को भी एक ट्वीट कर केंद्र पर कटाक्ष किया है. प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि एमएसपी का जिक्र इस बिल में क्यों नहीं है।

प्रियंका गांधी का ट्वीट

प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, अगर ये बिल किसान हितैषी हैं तो समर्थन मूल्य **MSP** का जिक्र बिल में क्यों नहीं है? बिल में क्यों नहीं लिखा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों का संरक्षण करेगी? सरकार ने किसान हितैषी मंडियों का नेटवर्क बढ़ाने की बात बिल में क्यों नहीं लिखी है? सरकार को किसानों की मांगों सुनना पड़ेगा।

बतादें कि इससे पहले सोमवार को भी प्रियंका ने सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने एमएसपी के मुद्दे पर ही सरकार को घेरा था। प्रियंका ने कहा था खेती-किसानी में कांग्रेस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडियों के सरंक्षण का प्रावधान किया जिससे कि किसानों का पूंजीपतियों के हाथों शोषण न हो। अगर **MSP** के किसान हितैषी प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं है तो भाजपा सरकार **MSP** के सरंक्षण को बिल में डालने से डर क्यों रही है?

नीम हकीम बने खतरा-ए-जान

■ जालंधर/रवि

चाहे आपको कोई भी बीमारी हो छोटी या बड़ी। कब्ज से लेकर गुप्त रोगों को ठीक करने तक का शर्तिया इलाज करने का दावा करते हैं राज्य भर में में जगह-जगह तंबू लगाकर बैठे झोलाछाप डाक्टर। व्यक्ति की नब्ज देखकर शरीर की तमाम कमजोरियां, बीमारियां, आदतों तक का विस्तार में विवरण पेश करने का भी यह झोलाछाप डाक्टर पक्का दावा करते हैं। ऐसे डाक्टर अक्सर सड़कों के किनारे लगे तंबू में बने देसी दवाखाना को चलाते हुए मिल जाते हैं। लेकिन यह डाक्टर अकसर नीम हकीम खतरा-ए-जान की कहावत को सच करते है। कई व्यक्ति इनके चंगुल में फंस कर जान से हाथ धो बैठे हैं, परन्तु सेहत विभाग व जिला प्रशासन ऐसे झोलाछाप डाक्टरों पर शिकंजा कसने के मूड में नहीं है। सेहत विभाग की कुंभकरणी नींद का फायदा उठाकर ही ऐसे झोलाछाप डाक्टर लोगों का आर्थिक व शारीरिक शोषण कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस तरह के झोलाछाप डाक्टर हिमालय, नैनीताल, हिमाचल प्रदेश से अनमोल जड़ी-बूटियां लाकर उनसे दवाएं बनाने का दावा करते हैं। इन दवाओं की इन मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है और इनका यह भी दावा है कि इनकी दवा खाने के बाद रोग जड़ से मुक्त होता है। इनसे लुभावने दावों को देखकर अकसर गरीब व अनपढ़ लोग इन के चंगुल में फंस जाते हैं। इन डाक्टरों के दावे सुनकर तो यहीं लगता है कि जैसे बड़े-बड़े अस्पतालों में बैठे डाक्टर भी इन झोलाछाप डाक्टरों का मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे खास बात तो यह है कि बड़े अस्पतालों में हमेशा किसी न किसी एक रोग का माहिर डाक्टर होता है, जैसे दांत माहिर, हृदय रोग माहिर, महिला रोग माहिर आदि, परन्तु यह सड़कों किनारे बैठे झोलाछाप डाक्टर खुद को हर रोग का माहिर बताते हैं।

डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, महिला रोग व गुप्त रोग को तो यह चुटकियों में ठीक करने का दावा करते हैं।

जिला स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते यह धंधा जोर शोर से चल रहा है। सेहत विभाग व प्रशासन झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ चुप्पी साधे बैठा है।

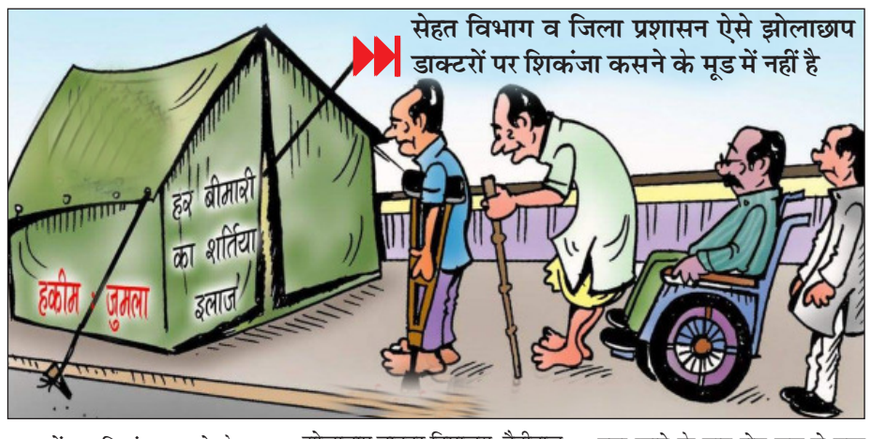

सेहत विभाग व जिला प्रशासन ऐसे झोलाछाप डाक्टरों पर शिकंजा कसने के मूड में नहीं है

कमिश्नरेट पुलिस जालंधर स्पैशल ऑपरेशन यूनिट द्वारा दो लड़कों से 6 ग्राम हेरोइन और नाजायज हथियार बरामद किये

■ जालंधर/रवि

कमिश्नरेट पुलिस जालंधर द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो लड़कों से 6 ग्राम हेरोइन और नाजायज हथियार 32 बोर देसी पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए।

इस बारे जानकारी देते हुए एसपी डिटेक्टिव कंवलजीत सिंह ने बताया कि सब इंस्पेक्टर अश्वनी कुमार स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ने सब्जी मंडी मकसूदा के पास गंदे नाले पर नाकेबंदी के दौरान 2 लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तभी शक के आधार पर उनको रोक कर उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनसे 6 ग्राम हेरोइन और नाजायज असला 32 बोर देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए मौके पर दोनों दोषियों को हिरासत में लिया गया जिसमें से राहुल कुमार उर्फ राहुल लोहच पुत्र रजिन्दर कुमार निवासी बी 1034 बस्ती मिट्ठू जालंधर के पास से 6 ग्राम हेरोइन और विपन कुमार उर्फ बबलू पुत्र राम कुमार वासी मकान न 259 कटहीरा मुहला बस्ती बावा खेल जालंधर के पास से नजायज हथियार 32 बोर देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। दोषियों के खिलाफ मुकदमा नंबर 174 तिथि 20-09-2020 अधीन 21/61/85 एनडीपीएस एक्टर 25-54-59 आर्म्स एक्ट पुलिस डिविजन नंबर 1 में दर्ज करवाया गया।

दखल

बाल अधिकारों की अनदेखी

तमाम विकास के बावजूद आज भी बच्चों को बचपन में ही श्रमिकों की तरह काम करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों से संबंधित सारे मामले केवल महिला एवं गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। अन्य मंत्रालयों को एक साथ मिल कर सामूहिक नीति बना कर कार्य करना चाहिए। मसलन, यातायात, सामाजिक न्याय, श्रम, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रमुख रूप से संयुक्त प्रयास करना चाहिए।

कहा जाता है कि बालक देश का भविष्य हैं। बालक की व्याख्या दो प्रकार से की गई है। एक तरफ कहा जाता है कि वे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं और दूसरी तरफ कहा जाता है कि बालक से एक ऐसा व्यक्ति है, जो स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकता। हमें बालक के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखना चाहिए। बालक के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता सदा महसूस की गई है क्योंकि बच्चा कमजोर होता है, समझ की कमी, परिपक्वता की कमी, क्षमता की कमी आदि के चलते उसके हितों की न सिर्फ अनदेखी होती, बल्कि बलात श्रम कराया जाता है, उसका लैंगिक शोषण भी किया जाता है। बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल अपहरण, शारीरिक और मानसिक शोषण की समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक कानून बनाए गए हैं, जिनकी समुचित जानकारी प्राप्त कर न सिर्फ हम उनके अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि बच्चों, उनके माता-पिता, आस-पड़ोस और फिर पूरे समाज को जागरूक भी कर सकते हैं।

वर्ष 1923 में सेव द चिल्ड्रन इंटरनेशनल यूनियन द्वारा बालकों के अधिकारों को नामांकित किया गया, जिसे 1924 में जिनेवा घोषणा-पत्र कहा गया, जिसमें बालक के सामान्य, भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बात कही गई और बताया गया कि जो बालक भूखा है, उसे भोजन दिया जाए, जो बीमार है उसका उपचार किया जाए और जो भटका है उसका सुधार किया जाए। 1959 में संयुक्त राष्ट्र की साधारण महासभा द्वारा बालकों के अधिकारों का घोषणा-पत्र स्वीकार किया गया, जिसमें बालकों के सर्वोत्तम हित की बात कही गई है। पर कोई भी घोषणा-पत्र राज्य पक्षकारों के ऊपर बाध्यकारी नहीं होता, इसीलिए 1989 में बाल अधिकारों की रूपरेखा बनी और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने, अमेरिका को छोड़ कर, उसे स्वीकार किया। इसमें मूल रूप से अधिकारों की बात कही गई है, जो उसके जीवन, अस्तित्व, विकास और सुरक्षा से संबंधित हैं।

इन अधिकारों की पृष्ठभूमि में अगर भारतीय विधियों की चर्चा करें तो सबसे पहले 'पीसीपीएनडीटी एक्ट' आता है, जो भ्रूण हत्या को अपराध बना कर बच्ची के जन्म को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। उसके बाद नवजात शिशु से लेकर दो वर्ष तक के बच्चे के लिए 'आईएमएस एक्ट' में बच्चे को माता द्वारा स्तनपान कराने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। सात वर्ष तक की उम्र के बालक को भारतीय दंड संहिता में पूरी तरह अपराध के दंड से मुक्त रखा गया है। फिर सात वर्ष से ऊपर और बारह वर्ष से नीचे के बालक को सीमित छूट प्रदान की गई है, जो इस आधार पर निर्भर करती है कि बालक में अपराध करने की समझ विकसित थी या नहीं। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे किशोर न्याय देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का लाभ मिलता है। निर्भया कांड के बाद इस अधिनियम में संशोधन किया गया। अगर बालक की उम्र 16 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से नीचे होती है, तो फिर उसकी समझ की परिपक्वता प्रभावी होती है। आगे के कानूनों में महत्वपूर्ण है- सबके लिए शिक्षा, जिसमें छह से 14 वर्ष तक के बालकों की मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया गया है। इन्हें लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए 'पॉक्सो एक्ट' है, तो तस्करी से बचाने के लिए 'अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम'।

बाल श्रम से बचाने 'बाल श्रम निवारण एवं विनियमन अधिनियम' है। बाल विवाह रोकने के लिए 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम' है। इन सबके बावजूद अपराध बढ़ रहे हैं, बालकों द्वारा भी और बालकों के विरुद्ध भी। नए संशोधन के अंतर्गत धारा 2 (14) के तहत 12 श्रेणियों के बालकों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता बताई गई है। हर अठारह वर्ष से नीचे के बालक को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। इसमें आवश्यकतानुसार नई श्रेणियों को भी शामिल किया जा सकता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में 'एक्सप्लॉइटेशन आफ चिल्ड्रेन इन आर्फनेज इन द स्टेट आफ तमिलनाडु बनाम भारत संघ' के मामले में न्यायाधीश मदन बी लोकुर एवं न्यायधीश दीपक गुप्ता ने कहा कि धारा 2(14) की परिभाषा अंतिम नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक बच्चे को बाल सुधार गृह में ही नहीं रखना चाहिए। बल्कि उनके दत्तक ग्रहण और देखभाल की व्यवस्था पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। जरूरी चीज है अभिभावकों द्वारा की जाने वाली देखभाल और पारिवारिक वातावरण।

जेजे एक्ट में धारा 2(14) (2) में भिक्षावृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और कहा गया है कि जो कोई भीख मांगता हुआ पाया जाता है या सड़कों पर रहता है, उसे भी सीएनसीपी माना जाएगा। पर 11 अगस्त, 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को अपराध के दायरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि यह उसकी गरिमा है कि वह चोरी नहीं कर रहा है। यानी अब जो बच्चा सड़क पर पाया जाएगा उसे ही सीएनसीपी कहा जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक बच्चा जो सड़क पर ही जन्म लेता है और सड़क पर ही रहता है, उसकी जिम्मेदारी उठाने वाले कहां तक इनका ख्याल कर पाते हैं, क्योंकि ये वे बच्चे हैं, जो अल्बर्ट के. कोहेन की भाषा में 'अपचारी' बन जाएंगे और प्रास्थितिक नैराश्य के कारण प्रतिक्रियावादी हो जाएंगे। अब जबकि ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर की संज्ञा दे दी गई है, तो ऐसे ट्रांसजेंडर बच्चों को भी सीएनसीपी की परिभाषा में शामिल करना चाहिए। ऐसी अवयस्क बच्चियां, जो यौन उत्पीड़न का शिकार होने के कारण गर्भवती हो जाती हैं और न चाहते हुए भी उन्हें बच्चे को जन्म देना पड़ता है, ऐसे बच्चों को दोहरे सीएनसीपी की संज्ञा दी जानी चाहिए।

अभी जेलों में बंद महिलाओं के साथ रह रहे छह वर्ष की उम्र तक के बालक के संबंध में भी विधि निश्चित नहीं हो पाई है। एक तरफ तो हम अठारह वर्ष से नीचे के बालक का वयस्क व्यक्ति के साथ संयुक्त विचारण भी नहीं करते और दूसरी ओर छह वर्ष के बालक बिना किसी अपराध के अपनी माताओं के साथ जेल के वातावरण में रहने को बाध्य होते हैं। यहां जेल मैनुअल में संशोधन की आवश्यकता है। 'खुशबू जैन बनाम रेल मंत्रालय' के मामले में सीएनसीपी बच्चों की देखभाल की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रेल मंत्रालय को सौंपी गई है। मगर इसके साथ ही आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों से संबंधित सारे मामले केवल महिला एवं गृह मंत्रालय तक सीमित नहीं रहने चाहिए। अन्य मंत्रालयों को एक साथ मिल कर सामूहिक नीति बना कर कार्य करना चाहिए। मसलन, यातायात, सामाजिक न्याय, श्रम, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रमुख रूप से संयुक्त प्रयास करना चाहिए।

इन सभी मंत्रालयों द्वारा बाल सहायता समूहों का गठन किया जाना चाहिए और मुक्तांगन की संकल्पना के आधार पर उनके आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। बाल कल्याण समितियों की संख्या भी प्रत्येक जिले की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाई जानी चाहिए, बाल कल्याण संस्थाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए और बाल सुधार इकाइयों के बढ़ते दायित्व को बांटने के लिए कुछ अन्य सहयोगी विभागों का सृजन करना चाहिए। इन सबके अलावा पूरे समाज को यह समझना पड़ेगा कि अगर एक भी बच्चा विधि विवादित होता है, तो उसका दंश समाज को झेलना पड़ता है, इसलिए सामूहिक अभिभावकत्व की संकल्पना का जितना अधिक विकास होगा, जितना ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता में और प्रत्येक संस्था अपनी संस्थागत क्षमता में बच्चों की देखरेख और संरक्षण कर पाएगी उतना ही वह देश समृद्ध, समर्थ और संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि समाज बच्चों के अधिकारों पर ध्यान दे और उसकी पूर्ति के लिए प्रयासों में जुटे। सिर्फ बातों से काम चलेगा नहीं।

विचार

कृषि बिल पर विवाद गलत

कृषि से जुड़े दो बिलों को राज्यसभा में पास कराने के दौरान जो हुआ, वह सही नहीं है। माना कि विपक्ष को अंदेशा है कि यह विधेयक किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा, मगर अभी सरकार जो कह रही है, उस पर भी पूरे देश को भरोसा करना ही होगा।

राज्यसभा में रविवार को केंद्र सरकार ने खेती से जुड़े दो बिल फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल ध्वनिमत से पास करा लिया। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बन जाएंगे। इससे पहले वोटिंग के दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने वेल में जाकर नारेबाजी की। तृणमूल सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने उपसभापति हरिवंश का माइक तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने सदन की रूल बुक भी फाड़ दी। सदन की कार्यवाही जारी रखने के लिए मार्शलों को बुलाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा से दोनों बिल पास होने के बाद 8 ट्वीट किए। किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा, भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। यह न केवल कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे।

दूसरे ट्वीट में उन्होंने फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी और सरकारी खरीददारी पहले की तरह जारी रहेगी। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समाप्त करने और कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों नए कृषि विधेयक लेकर आई है। हालांकि सरकार ने खंडन करते हुए कहा कि किसानों को बाजार का विकल्प और उनकी फसलों को बेहतर कीमत दिलाने के उद्देश्य से ये विधेयक लाए गए हैं। जो भी हो, सरकार और विपक्ष जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वह सब भविष्य के गर्भ में है। सरकार की बात सच होगी या विपक्ष की, यह सामने आएगा। मगर अभी सरकार जो कह रही है, उस पर भरोसा करना होगा। सरकार का कहना है कि एमएसपी का लाभ मिलता रहेगा और सरकारी खरीद जारी रहेगी तो ऐसा होगा। एमएसपी वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में फसल की कीमतें कम हो। तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव का किसानों पर असर न पड़े। उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। किसी फसल की बंपर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें कम होती है, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइज का काम करती है। यह एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। पीडीएस के जरिये जनता तक अनाज को रियायती दरों पर पहुंचाती है। पीडीएस के तहत देशभर में पांच लाख उचित मूल्य दुकानें हैं जहां से लोगों को रियायती दरों पर अनाज बांटा जाता है। एपीसी का नाम वर्ष 1985 में बदलकर सीएपीसी किया गया। यह कृषि से जुड़ी वस्तुओं की कीमतों को तय करने की नीति बनाने में सरकार की मदद करती है।

जनगणना से जुड़े बुनियादी सवाल

जरूरी है कि जनगणना की प्रक्रिया के वर्तमान स्वरूप को बदला जाए, जिससे गिनती में निरंतरता बनी रहे। इसके लिए न संस्थागत ढांचे की जरूरत है और न ही सरकारी अमले की। केवल गिनती की केंद्रीकृत जटिल पद्धति को विकेंद्रीकृत करके सरल करना है। गिनती की यह तरकीब ऊपर से शुरू न होकर नीचे से शुरू होगी। इस गिनती में जितनी पारदर्शिता और शुद्धता रहेगी उतनी किसी अन्य पद्धति से संभव नहीं है।

अगले साल होने वाली जनगणना एक ऐसा अवसर होगी, जब सरकार लोक-कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। सरकारी दावों के अनुसार देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है, सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म हो चुकी है और देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। ये घोषणाएं वास्तव में कितनी क्रियान्वित हुई हैं, इसकी पड़ताल जनगणना में की जाएगी। जनगणना पंजीकरण के अलावा आयुक्त संजय मानते हैं कि 'भौगोलिक और सामाजिक रूप से अनेक विविधताएं हैं। ऐसे में जनगणना एक ऐसा अवसर है, जिसमें सरकार देश के प्रत्येक नागरिक से सीधे रूबरू होती है। ऐसे में अगर योजनाओं के अमल में कोई विसंगति पेश आती है, तो उन्हें दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं।' वैसे, पंचवर्षीय योजनाएं जनगणना के आधार पर ही बनती हैं। इसलिए जो भी हकीकत सामने आए, उससे निपटने की जरूरत है।

देश की जनता के स्थायी व निरंतर गतिशील पंजीकरण की दृष्टि से जरूरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंपी जाए। गिनती के विकेंद्रीकरण का यह नवाचार जहां दस साला जनगणना की बोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश के पास प्रतिमाह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक और विश्वसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे। यह तरकीब अपनाना इसलिए भी जरूरी है कि यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत जिंदगी में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक बदलाव के लिए सर्वमान्य जनसंख्या के आकार और संरचना का दस साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। वैसे भी भारतीय समाज में जिस तेजी से लैंगिक, रोजगारमूलक और जीवन स्तर में विषमता बढ़ रही है, उसकी बराबरी के प्रयासों के लिए भी जरूरी है कि जनगणना की परंपरा में आमूलचूल परिपर्तन लाएं।

जनसंख्या के आकार, लिंग और आयु के अनुसार उसकी जटिल सरंचना का कुछ ज्ञान न हो, तो आमतौर पर अर्थव्यथा के विकास की कालांतर में प्रगति, आमदनी में वृद्धि, खाद्य पदार्थों व पेयजल की उपलब्धता, आवास, परिवहन, संचार, रोजगर के संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। अनुमान लगाना तब और कठिन होता है, जब देश और दुनिया में जनसंख्या वृद्धि को विस्फोटक स्थिति के रूप में आंका जा रहा हो। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या लगभग सात अरब हो चुकी है। वर्ष 2050 में आंकड़ा दस अरब तक पहुंच सकता है। इस आबादी का पचास प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा नौ देशों चीन, भारत, अमेरिका, पाक, बांग्लादेश, नाइजीरिया, कांगो, इथियोपिया और तंजानिया में होगा। जितनी तेजी से आबादी 19वीं सदी में बढ़ी है, उतनी तेजी से पहले कभी नहीं बढ़ी। 18वीं सदी के अंत तक दुनिया की जनसंख्या एक अरब के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई थी। इन शताब्दियों में जन्म दर अधिक होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर मंद थी।

प्रकृति पर निर्भर गर्भ निरोधकों से दूर और उपचार की आसान और सुलभ पद्धतियों से अनजान स्त्री-पुरुष बच्चे तो खूब पैदा करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर मर जाया करते थे। बीमारियों की पहचान और उपचार से नियंत्रण के चलते बीसवीं शताब्दी के पहले ही तीन दशकों में यह आबादी दोगुनी होकर करीब पौने दो अरब के आंकड़े को छू गई थी। भारत की जनसंख्या आजादी के साल 34.2 करोड़ थी। वर्ष 1947 से 1981 के बीच भारतीय आबादी की दर में ढाई गुना वृद्धि दर्ज की गई और आबादी 68.4 करोड़ हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर का आकलन करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में प्रति वर्ष एक करोड़ साठ लाख आबादी बढ़ जाती है। इस दर के अनुसार हमें देश की एक अरब तीस करोड़ लोगों की निश्चित जनसंख्या प्रारूप में गिनती करनी है, ताकि व्यक्तियों व संसाधनों के समतुल्य आर्थिक और रोजगारमूलक विकास का खाका खींचा जा सके।

जनसंख्या का यह आंकड़ा अज्ञात भविष्य के विकास की कसौटी पर खरा उतरे, मूलाधार वैज्ञानिक तरीके से की गई सटीक जनगणना ही है। हर दस साल पर होने वाली जनगणना में करीब बीस लाख कर्मचारी जुटते हैं। छह लाख गांवों, पांच हजार कस्बों, सैकड़ों नगरों और दर्जनों महानगरों के रहवासियों के द्वार-द्वार दस्तक देकर जनगणना का कार्य करना कर्मचारियों के लिए जटिल है। ऐसे में गिनती की जल्दबाजी में वे मानव समूह छूट जाते हैं, जो आजीविका के लिए मूल निवास स्थल से पलायन कर जाते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग होते हैं। बीते कुछ सालों में आधुनिक और आर्थिक विकास की अवधारणा के चलते इन्हीं जाति समूहों के करीब चार करोड़ लोग विस्थापन के दायरे में हैं।

इनसे रोशन गांव तो बेचिराग हैं, पर इन विस्थापितों का जनगणना के समय स्थायी ठिकाना कहां है, जनगणना करने आए दल को यह पता लगाना मुश्किल होता है। इसलिए जरूरी है कि जनगणना की प्रक्रिया के वर्तमान स्वरूप को बदला जाए, जिससे गिनती की निरंतरता बनी रहे। इसके लिए न भारी भरकम संस्थागत ढांचे की जरूरत है और न ही सरकारी अमले की। गिनती की केंद्रीकृत जटिल पद्धति को विकेंद्रीकृत करके सरल करना है। गिनती की यह तरकीब ऊपर से शुरू न होकर नीचे से शुरू होगी। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है, जिसका त्रिस्तरीय ढांचा विकास खंड और जिला स्तर तक है। करना सिर्फ इतना होगा कि तीन प्रतियों में एक जनसंख्या पंजी पंचायत कार्यालय में रख दी जाए। इसी पंजी की प्रतिलिपि कंप्यूटर में फीड हो। जिन गांम पंचायतों में बिजली और इंटरनेट की सुविधाएं हैं, वहां इसे जनसंख्या संबंधी वेबसाइट से जोड़ कर इन आंकड़ों का पंजीयन सीधे अखिल भारतीय स्तर पर हो सकता है।

परिवार को इकाई मान कर संरपच, सचिव और पटवारी को जबावदेही सौंपी जाए कि वे परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारियां जनसंख्या प्रारूप के अनुसार इन पंजियों में दर्ज करें। चूंकि ग्राम पंचायत स्तर का प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे को बखूबी जानता है, इसलिए इस गिनती में चित्र और नाम के स्तर पर भ्रम की स्थित नहीं होगी, जैसी कि मतदाता सूचियों और मतदाता परिचय-पत्र में हो जाती हैं। गिनती की इस प्रक्रिया से कोई वंचित भी नहीं रहेगा। गांव में किसी शिशु के पैदा होने और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की जानकारी तुरंत पूरे गांव में फैल जाती है, इसलिए इस जानकारी को अविलंब पंजी में दर्ज कर संबंधित व्यक्ति को जन्म और मृत्यु प्रमाण-पत्र देने का आधिकार भी ग्राम पंचायत को दिए जाएं।

पंचायत स्तर पर एकत्रित होने वाली यह जानकारी हर माह की एक निश्चित तारीख को विकास खंड स्तर पर पहुंचाई और उसकी एक प्रति विकास खंड कार्यालय में रखी जाए। इसे आधार बना कर इसका तत्काल कंप्यूटरीकरण किया जाए। जिले के सभी विकास खंडों की यह जानकारी जिला स्तर पर एकीकृत कर इस गिनती को कंप्यूटर में फीड किया जाए। इस तरह सभी विकास खंडों के आंकड़ों की गणना कर जिले की जनगणना प्रत्येक माह होती रहेगी। जिलावार गणना के डाटा को प्रदेश स्तर पर सांख्यिकीय कार्यालय में इकट्ठा कर प्रदेश की जनगणना का आंकड़ा भी प्रत्येक माह सामने आता रहेगा।

ट्विटर

मैं अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। कृषि विधेयक न केवल कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाएगा, बल्कि करोड़ों किसान सशक्त होंगे। एमएसपी व सरकारी खरीदारी जारी रहेगी।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। यह विधेयक किसानों से ज्यादा उद्योगपतियों को फायदा देगा। किसानों की दुर्दशा और बढ़ेगी।

राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

सत्यार्थ

ईश्वर का स्मरण

संत कबीर का जीवन बहुत ही सरल और सादगीमय था, पर उनके ज्ञान और संतत्व की ख्याति गजब थी। एक बार काशी के एक विद्वान जयंत आचार्य उनके पास पहुंचे। उस वक्त कबीर कपड़ा बुन रहे थे। कबीर को कपड़ा बुनते देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आचार्य सोच रहे थे कि कबीर के तो बड़े ठाट-बाट होंगे, पर उन्होंने देखा कि वे तो अत्यंत साधारण वेश में दिन भर दुनियादारी के कामों में व्यस्त रहते हैं। यह सब देखकर आचार्य ने उनसे पूछा- आप दिनभर कपड़ा बुनते रहते हैं, तो ईश्वर का

स्मरण कब करते हैं? तब कबीर बोले- तुम्हारे सवाल का जवाब मैं शब्दों में नहीं देता, उसका प्रायोगिक स्वरूप दिखाता हूं। कबीर ने उन्हें दिखाया कि एक औरत पानी का घड़ा सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। घड़े को उसने पकड़ नहीं रखा था, तो भी वह पूरी तरह संभली हुई थी। कबीर ने जयंत आचार्य से कहा- उस औरत को देखो। वह जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा। वह प्यासा होगा, उसके लिए वह पानी लेकर जा रही है। अब बताओ कि उसे घड़े की याद होगी या नहीं? जयंत बोले-उसे घड़े की याद नहीं होती, तो अब तक तो वह नीचे गिर चुका होता। तब कबीर बोले- यह साधारण-सी औरत सिर पर घड़ा रखकर रास्ता पार करती है, मजे से गीत गाती है, फिर भी घड़े का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। अब यह सब देख कर तुम्हें महसूस हो गया होगा कि मुझे परमात्मा के स्मरण के लिए अलग से वक्त निकालने की क्यों आवश्यकता नहीं है? कपड़ा बुनने का काम शरीर करता है, आत्मा नहीं। परमात्मा का सच्चा स्मरण तो हृदय से होता है, शरीर तो निमित्त मात्र है।

न्यूज

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक और सिख लड़की का अपहरण

इस्लामाबाद, (एजेंसी)। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 22 वर्षीय सिख लड़की लापता हो गई है। पुलिस ने अज्ञात अपहर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक यह घटना हाल में अटक जिले के हसनअब्दाल शहर में हुई। इसी शहर में सिखों का पवित्र धर्मस्थल प्रसिद्ध गुरुद्वारा पंजा साहिब है। डॉन अखबार के मुताबिक लड़की कचरा फेंकने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं आई। उसके पिता हसनअब्दाल में एक दुकान चलाते हैं। खबर में इस बात का जिक्र नहीं है कि यह घटना कब हुई। उप संभागीय पुलिस अधिकारी राजा फैयाज उल हसन के हवाले से बताया गया कि हसनअब्दाल पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर अज्ञात अपहर्ता के खिलाफ पाकिस्तान की दंड संहिता की धारा 365 बी के तहत अगवा करने (शादी करने के लिए अपहरण समेत) के तहत एक मामला दर्ज किया है।

मुंबई में निषेधाज्ञा, शिवसेना नीत सरकार की चाल: पाटिल

कोल्हापुर, (एजेंसी)। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने रविवार को आरोप लगाया कि मुंबई में धारा 144 लागू करना मराठा आरक्षण मुद्दे के पक्ष में आंदोलन को समाप्त करने के लिए शिवसेना नीत महा विकास अगाड़ी सरकार की एक चाल है।श्री पाटिल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने चार या अधिक व्यक्तियों को एकत्र होने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू की है लेकिन यह कोरोना की महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बल्कि मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर जारी प्रदर्शन को रोक लगाने के लिए है। सरकार के इस कदम से लगता है कि वि आंदोलन से घबरा गया है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए उसके पास कोई समाधान नहीं है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को एक तेजतर्रार नेता बताते हुए उनसे इस मुद्दे को सुलझाने और मराठा समुदाय के लिए 1,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने की अपील की।

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन

ओटावा, (एजेंसी)। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का टोरंटो में अपने घर पर निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। स्थानीय टेलीविजन रविवार को बताया कि श्री टर्नर का शुक्रवार की रात टोरंटो में अपने घर में निधन हो गया है। उन्हें 1984 में देश का 17वां प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। श्री टर्नर का जन्म 1929 को इंग्लैंड में हुआ था और वह बचपन में ही कनाडा आ गए थे। उन्होंने 1962 में कनाडा की राजनीति में प्रवेश किया और लिबरल पार्टी के लिए मॉन्ट्रियल सीट जीत हासिल की। वह अपने राजनीतिक करियर में 1968 से 1975 के दौरान प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के नेतृत्व में न्याय मंत्री और वित्त मंत्री सहित कई प्रमुख कैबिनेट पदों पर रहे। वह 1975 में अचानक पद छोड़ने के बाद 1984 तक राजनीति से दूर हो गए थे। श्री टर्नर ने कनाडा के इतिहास में दूसरे सबसे छोटे कार्यकाल 79 दिनों के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया।

सतर्क रहे! सुरक्षित रहे! कोरोना वायरस से सावधान रहे क्योंकि सावधानी ही बचाव हैं। कोरोना को धोना हैं।

नेपाल में चीनी सेना की घुसपैठ की रिपोर्ट के बीच ड्रैगन ने फेंका दोस्ती वाला जाल

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भेजा यह मैसेज

बीजिंग/काठमांडू, (एजेंसी)। चीन ने एक बार फिर नेपाल को मोहने के लिए बड़ी-बड़ी बातें की हैं, उसे विकास और मजबूत रिश्तों का सपना दिखाया है। नेपाल के संविधान दिवस के बहाने चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग ने नेपाली समकक्षों को मैसेज भेजा है। दूसरी तरफ रविवार को ही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीनी सेना ने नेपाली क्षेत्र में अतिक्रमण करके कई इमारतों को निर्माण कर लिया है।

नेपाली न्यूज वेबसाइट कांतिपुर के मुताबिक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि वह नेपाल-चीन संबंधों के विकास को बहुत महत्व देते हैं और इससे विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंध और व्यावहारिक सहयोग विकसित होगा। उन्होंने रविवार को संविधान दिवस पर अपने समकक्ष बिद्यादेवी भंडारी को एक बधाई संदेश भेजकर ये बातें कहीं।

शी ने पिछले साल की यात्रा को किया याद: शी ने पिछले साल उनके और राष्ट्रपति भंडारी की आपसी यात्रा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने मैत्रीपूर्ण रणनीतिक साझेदारी के राजनयिक संबंधों को आगे बढ़ाया। शी ने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के

खिलाफ दोनों देशों के सहयोग ने आपसी मित्रता को और मजबूत व गहरा किया है। उन्होंने कहा कि चीन-नेपाल संबंधों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को और विकसित करने और दोनों देशों के लोगों को अधिक लाभ पहुंचाने की इच्छा है।

पीएम केकियांग ने दी ओली को शुभकामनाएं

चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग ने रविवार को अपने समकक्ष केपी शर्मा ओली को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दीं और कहा कि नेपाल और चीन पारंपरिक रूप से मित्रवत पड़ोसी हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। ली ने यह भी कहा कि महामारी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में लड़ाई में नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि चीन नेपाल के साथ विकास और समृद्धि-उन्मुख रणनीतिक सहयोग, साझेदारी को और गहरा करना चाहता है।

तेज बारिश से कर्नाटक के कई हिस्सों में तबाही, उडुपी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित

बेंगलुरु, (एजेंसी)। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से काफी तबाही हुई है। खास तौर पर बारिश से तटीय उडुपी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। जहां घर तथा फसलें पानी में डूब गई हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने आपदा मोर्चा बल के कर्मियों को बचाव कार्य में लगाया है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि मलनाड, तटीय क्षेत्र और कुछ आंतरिक और उत्तरी जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार कर्नाटक में दक्षिणी-पश्चिम मानसून की दूसरी लहर राज्य से टकराई है, जबकि कोविड-19 महामारी के बीच उत्तरी कर्नाटक में आयी बाढ़ से राज्य अब तक ठीक से उबरा भी नहीं हैं। ऐसे में तेज बारिश ने एक बार फिर से लोगों को परेशानी में डाल दिया है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि बारिश से उडुपी में स्थिति गंभीर है, जहां कई गांव पानी में डूब चुके हैं, जिससे कई मकान धराशाई हो गए हैं। जिले की अधिकाश सड़कें बह गई हैं और खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। राज्य गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि उन्होंने उडुपी जिला प्रशासन को तत्काल राहत कदम उठाने के निर्देश दिये हैं। मंत्री ने कहा कि वह राजस्व मंत्री आर अशोक से बचाव कार्य में वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर लगाने का आग्रह करेंगे। वहीं कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी के अनुसार बचाव कार्य के लिए वहां एक हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है।

ड्रैगन ने दी ताइवान को धमकी

चीन ने कहा- अमेरिका से दूर रहो, नहीं तो कर लेंगे कब्जा

बीजिंग, (एजेंसी)। अमेरिका और ताइवान की दोस्ती से चिढ़े चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लेने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रैच के दौरे से बौखलाए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि शुक्रवार को लड़ाकू विमानों का ड्रिल चेतावनी देने के लिए नहीं था, बल्कि ताइवान पर कब्जे का रिहर्सल था। बता दें, चीन ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवानी क्षेत्र में लड़ाकू जेट समेत 19 विमान उड़ाए थे।

कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र में यह भी कहा गया है कि ताइवान की स्वतंत्रता खत्म होने वाली है। उसने कहा है कि वह युद्ध से पीछे नहीं हटता और इसके लिए उसने भारत सीमा का भी जिक्र किया है। चीनी अखबार ने कहा कि हर बार जब कोई अमेरिकी अधिकारी ताइवान आए तो पीएलए के लड़ाकू विमानों को आइलैंड की ओर और आगे बढ़ना चाहिए।

पुराने युद्धाभ्यासों से पीएलए ने कर लिया है हमले का अनुभव हासिल

शी चिनपिंग के मुखपत्र ने कहा है कि इस और पुराने युद्धाभ्यासों से पीएलए ने ताइवान पर हमले का अनुभव हासिल कर लिया है। यह ताइवान पर कब्जे को लेकर रिहर्सल है। केवल एक राजनीतिक वजह की आवश्यकता है, जिससे ये अभ्यास वास्तविक युद्ध में बदल जाएंगे। ताइवान स्ट्रेट में अशांति की सबसे बड़ी वजह अमेरिका से उसकी दोस्ती है। अमेरिका को यहां दे दूर रखने के लिए सैन्य सहित कोई भी कदम उठाया जा सकता है। चीनी सरकारी मीडिया ने कहा कि ताइवान और अमेरिका स्थिति का गलत आकलन न करें, यह न मानें कि यह अभ्यास दिखावा है। यदि वे उकसाते रहे तो युद्ध होना तय है, जिन्होंने भी हाल ही में चीन के दृढ़ संकल्प को कम आंका है, कीमत चुकाई है। चीन ने हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन को निर्णायक रूप से आगे बढ़ाया।

सैन्य अभ्यास ने भेजे दो अहम सिग्नल

ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि इस सैन्य अभ्यास ने दो अहम सिग्नल भेजे हैं। पहला यह कि यह विरोध अमेरिका और ताइवान के बीच मिलीभगत को लेकर है। दूसरा यह कि पीएलए की प्रतिक्रिया बेहद तेज है। ताइवान और अमेरिका ने तब तक क्रैच के दौरे को गोपनीय रखा, जब तक वे विमान में सवार नहीं हो गए। वह गुरुवार को ताइवान पहुंचे। पीएलए की ओर से एडवांस में सैन्य अभ्यास का ऐलान नहीं किया गया था।

पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके पूर्व सांसद शहाबुद्दीन

सीवान, (एजेंसी)। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन लंबी कानूनी प्रक्रिया के चलते तिहाड़ से पेरोल पर छूटकर नहीं आ सके। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीनके पिता को रविवार शाम छह बजे मगरिब की नमाज के बाद उनके पैतृक गांव प्रतापपुर के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। आपको बता दें कि तिहाड़ में बंद पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के पिता शेख मोहम्मद हसीबुल्लाह (90 वर्ष) का निधन शनिवार की रात हो गया था। बीते कई दिनों से शेख हसीबुल्लाह बीमार चल रहे थे। निधन की जानकारी मिलते ही रात में ही हजारों लोग शोक संवेदना जताने उनके गांव प्रतापपुर पहुंच गए। वहीं पिता के सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तिहाड़ में बंद पूर्व सांसद को पैरोल पर लाने की कानूनी कयावद रात में ही उनके वकीलों ने शुरू कर दी थी। राजद के कई बड़े नेता एवं कार्यकर्ताओं की फौज देर रात तक प्रतापपुर में डटी थी।

उच्चतम न्यायालय के लिए महिला न्यायाधीश को नामित करेंगे ट्रंप

नई दिल्ली, (एजेंसी)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रूथ बी गिन्सबर्ग के निधन के बाद रिक्त हुए पद के लिए किसी महिला उम्मीदवार को नामित करेंगे। ट्रंप ने शनिवार को उत्तरी कैरोलिना में एक चुनावी रैली में समर्थकों से कहा कि मैं अगले सप्ताह किसी को नामित करूंगा। मैं कह सकता हूं कि यह एक महिला होगी। कोई अगर मुझसे अभी पूछे तो मैं कहूंगा कि एक महिला पहले स्थान पर होंगी। गिन्सबर्ग का कैंसर से शुक्रवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थीं। अमेरिका की शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली गिन्सबर्ग दूसरी महिला थीं।

वाईएसआर सांसदों का प्रदर्शन

नई दिल्ली स्थित संसद भवन में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास, रविवार को अमरावती भूमि घोटाला मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने रविवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद हाथों में तख्तियां लिए हुए थे।

पायल घोष के यौन शोषण के आरोपों पर बोले अनुराग कश्यप- अभी तो बस शुरुआत है

नई दिल्ली, (एजेंसी)। एक्ट्रेस पायल घोष ने हाल ही में अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पायल का कहना है कि अनुराग ने उनके साथ जबरदस्ती की थी। इस पर अब अनुराग कश्यप ट्वीट कर लिखा है कि अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं। यह बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। यह भी पता है कि पता नहीं कहां-कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है।' अनुराग कश्यप ने आगे लिखा कि क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में। चलो कोई नहीं। मुझे चुप कराते-कराते इतना झूठ बोल गए की औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया।

अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण मामले की जांच करेगा एनसीडब्ल्यू

नयी दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने रविवार को कहा कि अभिनेत्री पायल घोष की ओर से बॉलीवुड के मशहूर निदेशक अनुराग कश्यप पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों की जांच की जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री शर्मा ने कहा कि उन्होंने अभिनेत्री पायल घोष से आयोग में शिकायत दर्ज करने के लिए कहा है और इस मामले की शिकायत संबंधित पुलिस थाना में भी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री ने ट्विटर पर फिल्म निदेशक पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिससे इस मामले की आयोग को जानकारी मिली। अध्यक्ष सुश्री शर्मा ने कहा कि एनसीडब्ल्यू में शिकायत करने की प्रक्रिया संबंधी लिंक अभिनेत्री को भेज दिया गया है। आयोग इस मामले की जांच करेगा।

फीस नहीं भरी तो स्कूल ने शिक्षा मंत्री की नातिन को क्लास लेने से रोका

रांची, (एजेंसी)। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा है। इस कारण कई परिवार अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने में असमर्थ हो गए हैं। इन हालातों को ध्यान में रखते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निजी स्कूलों को हिदायत दी थी कि वे फीस को लेकर नरमी बरतें। हालांकि, इस बार शिक्षा मंत्री को खुद ही स्कूल द्वारा फीस की मनमानी से जूझना पड़ा।

दरअसल, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन रिया की फीस जमा नहीं होने पर स्कूल ने उसे ऑनलाइन क्लास से हटा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा मंत्री तुरंत स्कूल पहुंचे और काउंटर पर खड़े होकर फीस जमा की। जब उनसे इस घटनाक्रम को लेकर सवाल किया गया तो महतो ने कहा कि वह मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक अभिभावक के तौर पर स्कूल पहुंचे थे।

दिल्ली के ई-रिक्शा चालक के बेटे ने लंदन में क्राउडफंड से जुटाई अपनी फीस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली के ई-रिक्शा चालक का बेटा कमल सिंह लंदन में फीस जुटाने के लिए क्राउडफंडिंग अभियान चला रहा है। 20 वर्षीय युवक लंदन स्थित प्रतिष्ठित इंग्लिश बैले स्कूल में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अपनी फीस जुटा रहा है।

स्कूल के एक वर्षीय पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सफल होने के बाद सिंह का सपना अंतर्राष्ट्रीय नृत्य मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का है। हालांकि, इसके लिए न केवल उन्हें फीस देने के लिए बल्कि लंदन में रहने के लिए काफी बड़ी राशि की जरूरत है।

सिंह ने कहा कि मेरा परिवार और मेरे कोच हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे निराश नहीं होने दिया। हालांकि मैं एक साल के पाठ्यक्रम की फीस- 8000 पांउड (करीब 7.60 लाख रुपए)- वहन नहीं कर सकता हूं। इसके साथ ही लंदन में रहने का भी खर्च है जो कम से कम एक हजार पाउंड (करीब 95 हजार रुपए) है।

एफएटीएफ की लटकी तलवार

फिर भी 21 आतंकियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही पाकिस्तान सरकार

इस्लामाबाद, (एजेंसी)। पाकिस्तान की गर्दन पर फाइनेंशल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की तलवार लटकी होने के बावजूद वह आतंकियों को पालने-पोसने और उन्हें सरकारी मेहमान बनाने से बाज नहीं आ रहा है। पाक सरकार अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम एवं पाक से संचालित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी रंजीत सिंह नीता सहित 21 आतंकियों को वीआईपी सुविधा दे रही है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाक के इस पाखंड पर चिंतित है, जो एक तरफ आतंकियों पर कार्रवाई का दिखावा करता है तो दूसरी तरफ उनकी फंडिंग कर रहा है। पाक सरकार 21 खूंखार आतंकवादियों को वीआईपी को मिलने वाली सुविधाएं दे रही हैं। इनमें वे आतंकी भी शामिल हैं, जिन पर पिछले महीने कथित प्रतिबंध लगाया गया। जिन आतंकियों को वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम, बब्बर खालसा इंटरनेशनल चीफ वाधवा सिंह, इंडियन मुजाहिद्दीन सरगना रियाज भटकल, आतंकवादी मिर्जा शादाब बेग और अफीफ हसन सिद्दीबापा शामिल हैं। इनमें कई ऐसे आतंकवादी शामिल हैं, जो भारत में मोस्ट वॉटेड हैं, लेकिन उन्हें शरण दे रहा है।

भेंट

फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात

फिल्म सिटी निर्माण को लेकर हुई चर्चा

लखनऊ, (एजेंसी)। महाराष्ट्र में हंगामे के बीच प्रख्यात फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मधुर की यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई। इस दौरान यूपी में फिल्म सिटी निर्माण को लेकर अहम चर्चा भी हुई। यूपी में फिल्म सिटी की घोषणा के बाद अभिनेत्री कंगना राणौत समेत कई फिल्मी हस्तियां सीएम योगी के ऐलान की सराहना कर चुके हैं।

मुलाकात में कई और मुद्दे भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी ने मधुर भंडारकर को राम मंदिर के प्रसाद के तौर पर प्रभु राम का सिक्का दिया, इसके अलावा रामचरित मानस, तुलसी माला और भव्य दिव्य कुंभ की कॉफी टेबल बुक प्रदान की। मुलाकात के बाद मधुर भंडारकर ने कहा कि जैसी फिल्म सिटी रामोजी राव हैदराबाद में है वैसी ही नोएडा में बनाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयास शुरू किया है। इंडस्ट्री में भी इससे काफी खुशी है।

सीएम योगी कर चुके हैं सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान

आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने कहा था कि देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है। उत्तर प्रदेश यह जिम्मेदारी को लेने को तैयार है। हम देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी तैयार करेंगे। इसकी स्थापना के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बेहतर होगा। फिल्म सिटी, फिल्म निर्माताओं को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराएगा। रोजगार सृजन की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी प्रयास होगा। उन्होंने इसके लिए भूमि के विकल्पों के साथ यथाशीघ्र कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

अभिनेत्री कंगना ने सीएम योगी के ऐलान का किया स्वागत

इसके बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत ने देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान का स्वागत किया है। घोषणा के अगले दिन शनिवार को कंगना ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कंगना ने ट्वीट किया कि योगी आदित्यनाथ जी की ओर से किए इस ऐलान की मैं सराहना करती हूं। हमें फिल्म इंडस्ट्री में कई सुधारों की जरूरत है। सबसे पहले हमें एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत है, जिसे भारतीय फिल्म उद्योग कहा जाए। हॉलीवुड को भी इससे फायदा मिल सके।

देश में तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री ने किया है शीर्ष स्थान हासिल

एक इंडस्ट्री, लेकिन कई फिल्म सिटी। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लोगों का मानना है कि भारत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो कि गलत है। तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री ने खुद को बेहद अच्छा साबित करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब यहां की फिल्में कई भाषाओं में रिलीज होती हैं। यहां तक कि कई हिंदी फिल्में रामोजी राव हैदराबाद में शूट की जाती हैं।

अतीक अहमद के कार्यालय पर चली योगी सरकार की जेसीबी

प्रयागराज, (एजेंसी)। पूर्व सांसद अतीक अहमद के कर्बला स्थित कार्यालय पर रविवार को विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। प्राधिकरण के अधिकारियों ने तीन जेसीबी की मदद से कार्यालय के दो हिस्सों को ध्वस्त करा दिया। अधिकारियों का कहना है कि नक्शे के विपरीत दो हिस्सों में अवैध निर्माण कराया गया था।

विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी शत शुक्ला के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम पुलिस फोर्स के साथ कर्बला पहुंची थी। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई कार्रवाई शाम चार बजे के बाद तक चली। सुरक्षा के मद्देनजर कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। विकास प्राधिकरण की टीम इसके पूर्व अतीक अहमद के कॉम्प्लेक्स, मकान समेत पांच अवैध निर्माण ध्वस्त करा चुकी है।

रबी की फसलों का MSP 50 रूपये लेकर 300 रूपये तक बढ़ा कर मोदी सरकार ने दिया किसानों को तोहफा–सुशील शर्मा

जालंधर/रवि

केंद्र की मोदी सरकार तथा कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के हित में पास किए गए कानूनों में किसानों को और अधिक सशक्त करते हुए उनकी रबी की फसलों गेंहू, जौं, सरसों, चना, कुसुम व मसूर की फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा कर किसानों को तोहफा दिया है । यह कहना है भाजपा जिला जालंधर के अध्यक्ष सुशील शर्मा का ।उन्होंने कहा कि (MSP) की आढ़ लेकर मोदी सरकार द्वारा पास किए गए कृषि संबंधी कानूनों का विरोध करने वाले सभी विपक्षी दलों तथा अन्य लोगों के मुंह पर तमाचा है ।

उन्होंने विरोध करने वाले तथा सड़कों पर उतरे सभी लोगों को इन बिलों को विस्तार से पढ़ने की अपील की और कहाकि पहले बिलों को अच्छी तरह पढ़िए फिर सवाल कीजिए। सुशील शर्मा ने कहा कि सरकार हर फसल सीजन से पहले (CACP) यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है। यदि किसी फसल की बंपर पैदावार हुई है तो उसकी बाजार में कीमतें बिचौलियों द्वारा कम कर दी जाती हैं, तब (MSP) किसानों के लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइज का काम करती है। उन्होंने कहाकि रूस्क वह गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है। भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हों। उन्होंने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कई बार साफ कर चुके हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खत्म नहीं होगा । उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कंट्रोल अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है, वे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, किसानों की आय दोगुनी एवं उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य के लिए मोदी सरकार वचनबद्ध है ।उन्होंने कहाकि मोदी सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय द्वारा तय किये गए रबी के सीजन की फसलों में गेंहू के समर्थन मूल्य में 50 रूपये प्रति क्विंटल, जौ 75 रूपये प्रति क्विंटल (1925 से बढ़ा कर 1975), सरसों 225 रूपये प्रति क्विंटल (1525 से बढ़ा कर 1600), चना 225 रूपये प्रति क्विंटल (4425 से बढ़ा कर 4650), कुसुम 112 रूपये प्रति क्विंटल (4875 से बढ़ा कर 5100) व मसूर 300 रूपये प्रति क्विंटल (4800 से बढ़ा कर 5100) इजाफ़ा किया गया है। जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के दिशा–निर्देश पर किसान मोर्चा के कार्यकर्ता अगले एक महीने में प्रदेश के गाँव–गाँव में जाकर किसानों को कृषि संबंधी विधेयकों के बारे में जागरूक करेंगे तथा किसानों के सवालों के जवाब भी देंगे। अगर किसान संगठनों को कृषि संबंधी विधेयकों के बारे में कोई शिकायत है तो वह प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों से संपर्क कर सकता है और प्रदेश भाजपा उनकी शिकायत के निवारण के लिए उनकी बात केंद्र सरकार से करवा सकती है। इस अवसर पर जिला महामंत्री भगवंत प्रभाकर एवं राजीव ढींगरा उपस्थित थे ।

SPORTS PLANET

एबी डिविलियर्स ने कहा कि वह खुद पांच महीने के ब्रेक के बाद इस तरह के फार्म से हैरान हैं।

स्पोर्ट्स प्लैनट

डिविलियर्स अपने फॉर्म से हैं हैरान, पडिकल की तारीफ में कही यह बात

■ दुंबई/ब्यूरो

आईपीएल के पिछले सीजन में अपने शुरुआती 6 मैच हारने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंग्लोर ने 13वें सीजन में जीत के साथ आगाज किया। आरसीबी ने अपने पहले मैच में हैदराबाद को 10 रन से मात दी। आरसीबी की जीत में अहम योगदान पडिकल, डिविलियर्स के अर्धशतक और चहल के तीन विकेट का रहा। लेकिन डिविलियर्स अपनी इस पारी से खुद हैरान हैं।

सनराजइर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में अर्धशतक जमाने वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने कहा कि वह खुद पांच महीने के ब्रेक के बाद इस तरह के फार्म से हैरान हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ने 30 गेंद में 51 रन बनाये जिससे आरसीबी ने पांच विकेट पर 163 रन जोड़े। डिविलियर्स ने कहा, मैं खुद हैरान हूं। दक्षिण अफ्रीका में हमने एक प्रतिस्पर्धी मैच खेला था जिससे थोड़ा आत्मविश्वास आया था। एक 36 वर्ष का खिलाड़ी जिसने पांच छह महीने से ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली , वह युवाओं के बीच आकर ऐसा खेले तो यह अच्छी शुरूआत है। खुश हूं कि बेसिक्स पर अडिग रहा।

डिविलियर्स ने पहले ही आईपीएल मैच में अर्धशतक जमाने वाले देवदत्त पडिकल की तारीफ की। उन्होंने कहा, वह काफी शर्मीला और कम बोलने वाला लड़का है। वह काफी प्रतिभाशाली है और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।

बता दें कि देवदत्त पडिकल ने अपनी कामयाबी का श्रेय विराट कोहली को दिया है।

पडिकल का कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान विराट कोहली से जो सीख मिली उसका फायदा उन्हें हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में हुआ।

पंजाब की महिलाएं सरबत सेहत बीमा योजना का लाभ लेने में पुरुषों की अपेक्षा आगे–बलबीर सिद्धू

44,000 से अधिक मरीज़ों को इलाज मुहैया करवा के बठिंडा पहले स्थान पर रहा

3.95 लाख से अधिक मरीज़ों को 455.46 करोड़ रुपए की मुफ्त इलाज सहूलतें मिलीं

■ चंडीगढ़/ब्यूरो

इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं ने 51 प्रतिशत और पुरुषों ने 49 प्रतिशत लाभ लिया है। सरकारी स्कीमों के प्रति जागरूकता दिखाते हुये पंजाब की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले आयुषमान भारत–सरबत सेहत बीमा योजना (एबी–एसएसबीवाई) के अधीन और ज्यादा लाभ हासिल किये हैं। जन–समर्थकी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों के द्वारा दूसरे और तीसरे दर्जे की स्वास्थ्य सेवाएं लाभपात्रियों को घर–घर मुहैया करवाना है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने और ज्यादा जानकारी देते हुये बताया कि 767 प्राईवेट और सरकारी अस्पतालों को सूचीबद्ध करके पंजाब देश का सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला राज्य बन गया है, इस स्कीम के अंतर्गत 3.95 लाख से अधिक मरीज़ों को 455.46करोड़ रुपए की मुफ़्त इलाज सहूलतें मुहैया करवाई गई हैं।

उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 46लाख ई–कार्ड जारी किये जा चुके हैं। अब तक 6700 से अधिक दिल की सर्जरियां, 1 लाख डायलसिस, 7600 नवजात बच्चों का इलाज, 4000 घुटने बदलने के साथ–साथ 9300 से अधिक कैंसर मरीज़ों को एबी–एसएसबीवाई के अधीन इलाज का लाभ मिला है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंजाब में सबसे अधिक लाभपात्रियों का स्कीम के अधीन इलाज का लाभ लेने के मामले में 44,000 से अधिक मरीज़ों के साथ जिला बठिंडा अग्रणी है। इसी तरह राज्य में जिला लुधियाना ने सबसे अधिक 4.25 लाख ई–कार्ड बनाऐ हैं।

ए.बी–एस.एस.बी.वाई के लाभ सम्बन्धी दो घटनाओं का ज़िक्र करते हुये उन्होंने कहा कि तालिब ख़ान जो एक मज़दूर के तौर पर काम करता है, कई सालों से घुटने और कमर के दर्द से पीड़ित था और काम करने से असमर्थ था। उसे अपने परिचित से ए.बी –एस.एस.बी.वाई संबंधी पता लगा और उसने स्थानीय मैडीकल प्रैटीशीनर की सहायता से अपना ई –कार्ड बनवाया।

इसके बाद वह सिवल अस्पताल मानसा गया जहाँ उसका घुटने बदलने सम्बन्धी इलाज किया गया। इस सर्ज़री से ठीक होने के उपरांत उसने इस स्कीम के अंतर्गत हिप्प रिप्लेसमैंट का इलाज करवाया।

तालिब ख़ान ने बताया कि वह अपने आप को परिवार पर बोझ समझता था क्योंकि वह काम करने से असमर्थ था। ए.बी –एस.एस.बी.वाई की सहायता से दो बड़ी सर्जरियां की गई जिन पर उसका 5–6लाख का खर्चा आना था। उसने कहा कि उसे पहले की तरह होने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसे अपनी आर्थिक बदहालियों का पता था परन्तु इस स्कीम से वह मुफ़्त में घुटने और कमर की सर्ज़री करवाने के योग्य हो गया। वह कुछ महीनों में दोबारा काम करने के योग्य होने की उम्मीद कर रहा है और महसूस करता है कि एक नयी ज़िंदगी मिल गई है।

इसी तरह पेशे से चालक जैतो (फरीदकोट) के बलविन्दर सिंह को छाती में बहुत दर्द महसूस हुआ है और उसको एमरजैंसी में दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टी –स्पैशलिटी अस्पताल (बठिंडा) ले जाया गया। बलविन्दर और उसका परिवार ए.बी –एस.एस.बी.वाई. से अवगत था और उन्होंने पहले ही कार्ड बनवा लिया था। इस स्कीम के अधीन उसे अस्पताल में दाख़िल करवाया गया और इस स्कीम की सहायता से उसका मुफ़्त इलाज किया गया और अब उसने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है।

ए.बी –एस.एस.बी.वाई. की विशेषताओं पर रौशनी डालते हुये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत किसान, छोटे व्यापारी, रजिस्टर्ड निर्माणर श्रमिक, मान्यता प्राप्त पीले कार्ड धारक पत्रकार, स्मार्ट राशन कार्ड धारक प्रति परिवार 5 लाख प्रति साल के स्वास्थ्य बीमे के हकदार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में ए.बी. –एस.एस.बी.वाई. ने 20 अगस्त, 2020 को अपने लागूकरन का एक साल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नतीजे के तौर पर, दूसरे साल में स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को 1579 तक बढ़ाया गया है।

सनराइजर्स को लगा बड़ा झटका, चोट के चलते मिशेल मार्श हो सकते हैं आईपीएल 2020 से बाहर

■ दुंबई/ब्यूरो

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सीजन में अपने पहले मैच ही सनराइजर्स हैदराबाद को हार का सामना पड़ा है. विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने हैदराबाद को 10 रनों की मात दी। मैच में हार के अलावा हैदराबाद को एक बड़ा झटका लगा है। फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श गेंदबाजी करते हुए चोटिल गए हैं. इस चोट के चलते मार्श आईपीएल के 13वें सीजन से बाहर हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान मार्श की एड़ी में चोट आई थी। बैंगलोर के खिलाफ 5वां ओवर करने के लिए कप्तान डेविन वार्नर ने मार्श को गेंदबाजी के लिए बुलाया. मार्श सिर्फ चार गेंद ही फेंक सके. दरअसल अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ही आरोन फिंच का ड्राइव रोकने के चक्कर में उनका पैर मुड़ गया था. दर्द के बावजूद मार्श ने दो और गेंद फेंकी, लेकिन इसके बाद वो गेंदबाजी नहीं कर सके. हालांकि मार्श चोटिल होने के बावजूद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे. वे 10वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और नजर आया कि वो कितने दर्द में हैं।

टीम से जुड़े एक सूत्र ने कहा है कि यह गंभीर चोट लग रही है और मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता है कि वो आगे के मैचों में खेल सकेंगे या नहीं. अगर मार्श आईपीएल का हिस्सा नहीं होते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बड़ा झटका हो सकता है। मार्श के बाहर होने पर आखिरी एकादश में अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर मोहम्मद नबी को जगह मिल सकती है।

एनआईटी जालंधर ने माल की आसान ढुलाई के लिए रोबोटिक मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का आविष्कार किया

■ जालंधर/रवि

आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद डॉ बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), जालंधर ने रोबोटिक मॉड्यूलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (आरएमटीएस) का आविष्कार किया है। यह आविष्कार कुछ अन्य डोमेन में उपयोगी होने के अलावा भारत सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। रोबोटिक और ऑटोमेशन में विशेषज्ञता रखने वाले एसोसिएट प्रोफेसर डॉ के एस नगला द्वारा आविष्कार किया गया यह सिस्टम, विभिन्न डोमेन जैसे कि शहर के कचरे के परिवहन, कृषि सामान, गोदाम में माल के परिवहन और किसी भी निर्माण इकाई में भी उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के मॉड्यूल का उपयोग अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले दशक के भीतर उक्त उत्पाद घरों से कचरा उठाने के लिए स्मार्ट शहरों का एक आवश्यक हिस्सा होगा। यह बुद्धिमान प्रणाली, जो पहियों पर चलती है, को नवीनतम आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) तकनीक का उपयोग करके कंप्यूटर और मोबाइल फोन से जोड़ा जा सकता है जो इसे ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। स्मार्ट शहरों की परियोजना के संदर्भ में, पर्यावरण के अनुकूल बंद वाहनों में घर से कूड़े को डंप करने के लिए इसका बहुत बड़ा उपयोग है, वर्तमान में कई स्थानों पर खुले कचरा ट्रकों का उपयोग किया जाता है। आरएमटीएस को लंबी एयर कंडिशन्ड ट्यूब में सब्जियों सहित खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए बदला जा सकता है। यह बहुत कम लागत पर अनाज के बैग का प्रबंधन करने के लिए खाद्य निगम के गोदामों में कुशलतापूर्वक रखा जा सकता है। इसका उपयोग वायु बंदरगाहों या समुद्री बंदरगाहों पर भी किया जा सकता है। शहर के जटिल हिस्से में मलबे को हटाने के लिए मॉड्यूल की एक श्रृंखला बनाकर भूकंप के दौरान इस मॉड्यूल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। एनआईटी, जालंधर के निदेशक प्रोफेसर एल के अवस्थी ने कहा कि पेटेंट दायर किया गया है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को पुणे स्थित एक कंपनी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

सेवा सप्ताह में ओबीसी मोर्चा जालंधर ने चलाया स्वच्छता अभियान

■ जालंधर/रवि

भारतीय जनता पार्टी हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाती है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनेक प्रकार की सेवाएं करते है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जालंधर ने इस साल मोर्चा अध्यक्ष एड दविंदर लुबाना डिंपी की अध्यक्षता में शहर के अलग अलग स्थानों पर स्वछता अभियान के तहत पूरा सप्ताह साफ सफाई की और आज सेवा सप्ताह के आखिरी दिन वर्कशॉप चौक में स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के आदर्श,मार्गदर्शक है उनकी प्रतिमा और चौंक की साफ–सफाई कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया। सेवा सप्ताह के आखरी दिन समाप्ति पर एड. दविंदर लुबाना डिंपी ने कहा कि यह सभी कार्यक्रम भाजपा ओबीसी मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और उनके सहयोगी साथियों की वजह से ही सफल हो पाए हैं इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा जी मोर्चे के कार्यकर्ताओ की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे। इस मौके पर एड. दविंदर लुबाना डिंपी,प्रताप सिंह, ललित बब्बू,अरुण कुमार, करमजीत परमार,गुरदेव सिंह,गुरमीत सिंह,कर्ण कुमार, रोहित, रिंकू, विकी,नरेश,मनोज,विनोद कुमार,राज कुमार,कर्ण आदि मौजूद थे।

विजीलैंस ने 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ए.एस. आई रंगे हाथों दबोचा

■ जालंधर/रवि

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज सिटी पुलिस थाना ज़िला होशियारपुर में तैनात ए.एस.आई. दविन्दर कुमार को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त ए.एस.आई को शिकायतकर्ता दीपक नखवाल निवासी समिति बाज़ार, होशियारपुर की शिकायत पर पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने विजीलैंस ब्यूरो को अपनी शिकायत में बताया कि उसकी लॉटरी की दुकान पर काम करते कर्मचारी को पुलिस हिरासत में से रिहा करने के बदले उक्त ए.एस.आई द्वारा 4,000 रुपए की माँग की गई है। विजीलैंस ने शिकायत की पड़ताल के उपरांत उक्त दोषी ए.एस.आई. को दो सरकारी गवाहों की हाज़िरी में 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि दोषी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की अलग–अलग धाराओं के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो के थाना जालंधर में मुकद्मा दर्ज करके अगली कार्यवाही आरंभ कर दी है। इस शिकायत की करवाई के लिए एसएसपी विजीलैंस दलजिंदर सिंह ढिल्लों जालंधर द्वारा डीएसपी निरंजन सिंह की अगुवाई में जालंधर यूनिट से इंस्पेक्टर राजविंदर कौर,सब इंस्पेक्टर गुरबक्श सिंह, ए.एस.आई. जगरूप सिंह, ए.एस.आई गुरजीत सिंह, ए.एस.आई. रंजीत सिंह आदि अन्य अधिकारी मौजूद थे।

चोरी की वारदातों को नकेल डालने में फेल साबित हो रही पंजाब पुलिस

■ जालंधर/रवि

देश की सबसे दमदार अपने आपको मानने वाली पंजाब पुलिस इस समय अपराधियों के आगे बोना साबित हो रही है।

इसके एक नहीं अनेकों उदहारण प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित खबरों को देखकर या पढ़कर साबित हो रहा है हाल ही में कोरोना महामारी ने लोगों के भूखमरी जैसे हालात पैदा कर दिए जिससे युवा पीढ़ी बेरोज़गारी की वजह से अपराध और नशे के रास्ते को चुन रहे जो आने वाले दिनों में और घातक साबित हो सकता है।

पिछले एक हफ्ते में महिलाओं से पर्स छीनने की, गरीब व्यक्ति से मोबाइल छीनने की और फगवाड़ा के गांवों चेहरु–मेहरु में कई वारदातों की सी.सी. टीवी फुटेज मुहैया करवाई गई परन्तु पंजाब पुलिस अपराधियों को नकेल डालने में पूरी तरह फेल है और लोग डर के साये में जीने को मजबूर है इसमें कुछ भ्रष्ट अफसरों की मिलीभगत की भी जांच का विषय है।

डेविएट कॉलेज में कुक का काम करने वाले को दातार दिखा कर मोबाइल छिना

जालंधर/रवि

चोरी की वारदाते हर रोज़ सुनने में सामने आ रही है इसी तरह का एक मामला सामने आया है आज सुबह राजू पिता का नाम अयोध्या जो की डेविएट कॉलेज में कुक का काम करता है और ग्रीन फील्ड एरिया में रहता है अपने घर से सुबह तकरीबन 7.30 बजे काम पर निकला । उसी वक्त कपूरथला रोड नज़दीक कोहिनूर फैक्ट्री के पास दो मोटरसाइकिल सवार लड़को ने रोका जिनके हाथ में एक तेज़धार हथियार(दातार) था वह उसको हथियार दिखा कर उसका मोबाइल ओपपो ए 3.5 छिन कर फरार हो गए। उसने पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा दी है और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

शहर में पुलिस से नहीं डर रहे मोटरसाइकिल सवार लुटेरे

जालंधर। चोरों के होंसले दिन–ब–दिन बढ़ते ही जा रहे हैं वही आज मामला सामने आया पुलिस डिवीजन नंबर 2 के पास पढ़ते एरिया गोपाल नगर में साहिल मोबाइल शॉप के पास वहां दो मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने एक महिला का पर्स छीनकर हुए फरार पूछने पर अक्षय निवासी ग्रेटर कैलाश जालंधर मकान नंबर 579 ने बताया कि वह आज अपनी मम्मी निरू गुप्ता वाइफ ऑफ राजिंदर गुप्ता के साथ मोबाइल हाउस में ग्लास कार्ड डलवाने आए थे इतने में उन्होंने अपनी मम्मी की आवाज सुनी और बाहर भागे और देखा कि दो मोटरसाइकिल सवार लड़के उनकी मम्मी से पर्स छीन कर फरार हो गए। अक्षय पुत्र रजिन्दर गुप्ता ने बताया की पर्स में 1000 हजार की नगदी घर की चाबिया और गोल्ड रिंग एटीएम कार्ड और जरूरी कागज थे ।

दिनदहाड़े चोरों ने की वारदात महिला से पर्स छीन कर हुए फरार

जालंधर। दिन–ब–दिन शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है ऐसा ही एक मामला सामने आया जब एक महिला स्कैनिंग करा कर घर लौट रही थी तभी अवतार नगर के पास बैंक ऑफ इंडिया के बाहर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए लुटेरों ने पर्स खींच कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना भार्गव कैंप की पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस की पूछताछ के दौरान संतोष रानी पत्नी दर्शन लाल निवासी कृष्ण नगर ने बताया कि वह आज अपनी बेटी के साथ विनय स्कैनिंग सेंटर में स्कैनिंग कराकर रिक्शे पर सवार होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे जैसे ही वह अवतार नगर गली नंबर 13 बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचे उसी समय मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने उनका पर्स खींचकर फरार हो गए जिसमें 1500 रुपए नकदी और एक मोबाइल था।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN-453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)

Editor: ATUL SHARMA*

*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.